मध्यप्रदेश के रीवा जिले के गांव में आज भी पुलिस दमन जारी है

अलोका कुजूर
रांची झाड़खण्ड

मध्यप्रदेश के रीवा जिला में आदिवासी और दलित समूदायों का क्षेत्र रहा हैं वहां आदिवासी और दलित का संघर्ष लम्बे समय से अपने पुस्तैनी जमीन को लेने के लिए संधर्ष जारी रहें हैं। विगत कई सालों से रीवा वनों में वन विभाग गैरकानूनी तरीके से विस्थापित करती आ रही है। परन्तु अपनी उसी जमीन पर हर साल वापस आ जाते हैं।

2006 को भारत सरकार ने वनाधिकार अधिनियम पारित किया । यह नया कानून कहता हैं कि देश मं वन क्षेत्र से सन 2005 की दिसम्बर से पहले काबिज आदिवासयों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसकी जानकारी से उत्साहित इन परिवारो ने अपनी जमीन पर अपना अधिकार स्थापित करने के जिए मढ़ई बांध ली। इसके बाद जिला प्रशासन से इसे पुक्ता करने की वार्ता चल रही थी और 18 अप्रैल 2007 को संतोषजनक वार्ता हुई तथा जिला क्लेक्टर उन जमीनों पर पट्टा देने के लिए जांच पड़ताल के लिए सहमत भी हो गये। परन्तु अगले दिन, 19 अप्रैल 2007 को वहां बसे दबंग सामन्ती लोग जिनकी नजर उस जमीन पर थी, उन्होने गुस्सा होकर वहां पर 1000 पुलिस फोर्स भेज कर वहां के लोगो पर पर गोलीयों चला दी इसका मुकाबला लोगों ने खासकर महिलाओं ने जम कर किया। महिलाओं ने आगे आकर पुलिस को मार भगाया। पहले दौर पर पुलिस भाग ये पर तुरन्त बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथवहां वापस आये तभी गांव के लोगों के घर जला दिये, यही नही दुकाने लूट ली। अपने संघर्ष को चलाने हेतू लोगों द्वारा इकट्ठा की गई धनराशि भी पुलिस ने छीन ली। उपर से गोली भी चलाई पुलिस की गोली से कई लोग घायल होगये, महिलाओं ने खूब हिममत दिखाई और दुबारा पुलिस को मार भगाया। इसके बाद प्रशासन ने वहां और अधिक पुलिस फोर्स भेजकर घेरा बंदी कर दी। पुलिस द्वारा 600 ग्रामीणों के खिलाफ एफ. आई . आर . दर्ज किये।

इस घटना से कई परिवार के घर तोड. दिये गये जिससे गांव में आधें से अधिक आदिवासी और दलित बेघर हो गये। पुलिस वाले लगातार गांव के दंबग लोगो के साथ गांव में आतंक मचाया हुआ

शब्द 342

अलोका कुजूरए रांची झाड़खण्ड
झाड़खण्ड जंगल बचाओ आंदोलन
से जुडी हुई है।